1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Karnataka	45	11.14	40	6.48	74	7.20
11.	Maharashtra	162	11.10	186	17.13	140	15.73
12.	Madhya Pradesh	200	26.51	209	27.82	281	34.26
13.	Punjab	638	45.83	1342	96.40	1870	139.32
14.	Rajasthan	170	10.30	208	25.00	202	34.11
15.	Tamil Nadu	15	1.84	45	18.03	29	4.23
16.	Uttar Pradesh	127	11.34	304	15.94	1250	153.50
17.	West Bengal	—	1.45	—	4.74	—	5.32
		3000	220.08	4832	334.22	7799	501.66

To be answered on the 2nd December, 1983

Trade Relations with China

1791. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have taken steps for the establishment of trade relations with China ;

(b) if so, the items on which trade ties have been started between both the countries; and

(c) the details of the export import agreement made between these two countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) Trade between India and China was resumed in June, 1977.

(b) During the last few years India has exported shellac, iron ore and concentrates, cotton, sugar, iron and steel items and chrome ore to China. Recently contracts for export of shellac and chrome ore to China have been signed. The items imported by India from China during the last few years are spices, silk, chemicals and related products, textile yarn, miscellaneous non-ferrous metals and machinery and transport equipment.

(c) There is no Trade Agreement between India and Peoples Republic of China.

अन्तरिम राहत से भविष्य निधि की कटौती ।

1792. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सत्र के दौरान उन्होंने चौथे वेतन आयोग के गठन और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के भुगतान की घोषणा की थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के भुगतान सम्बन्धी घोषणा में अन्तरिम राहत को भविष्य निधि की कटौती के प्रयोजन के लिये "वेतन" माने जाने का कोई उल्लेख नहीं था;

(ग) क्या उक्त घोषणा के बाद रेलवे बोर्ड ने दिनांक 2 अगस्त, 1983 के अपने पत्र संख्या पी० सी० III-83/पी० सी०-IV/3 (आई० आर०) के माध्यम से यह आदेश जारी किया था कि अन्तरिम राहत को "वेतन" के रूप में माना जाएगा और उसमें से भविष्य निधि की धनराशि काटी जानी चाहिये और तदनुसार भविष्य निधि नियमों के अनुसार अन्तरिम राहत की धन राशी में से भविष्य निधि की कटौती की गई है; और